

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

: आयुक्त (अपील -I) का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, :
: सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, :
: आंबावाडी, अहमदाबाद- 380015. :

क फाइल संख्या : File No : V2(39)15 and 16/Ahd-III/2015-16/Appeal-I

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-195 to 196-16-17

दिनांक Date : 22.12.2016 जारी करने की तारीख Date of Issue 10/1/17

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals-I) Ahmedabad

ग _____ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I आयुक्तालय द्वारा जारी मूल
आदेश सं _____ दिनांक : _____ से सृजित

Arising out of Order-in-Original: AS PER ORDER Date: AS PER ORDER
Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Kalol, A'bad-III.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Umasree Textplast Pvt.Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

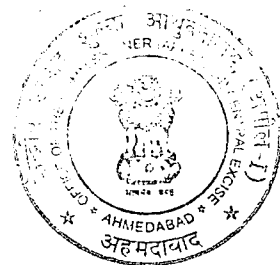
(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.



ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- णबी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

(a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

(ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैनटल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

(b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 39फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 24) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

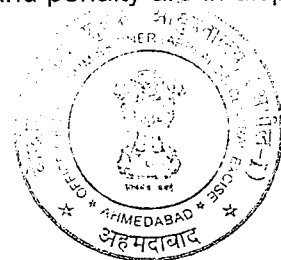
Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस s.dWR मे., इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

M/s. Umasree Texplast Private Limited, 728/1, Village Matibhoayan, Tal. Kalol, District Gandhinagar, Gujarat [for short -'appellant'] has filed two appeals, the details of which are as follows:

Sr. No.	OIO No. and date	Amount of rebate rejected vide the OIO	OIO passed by	Appeal No.
1	5606-5608/CE/ Reb/DC/15-16 dated 18.3.2016	Rs. 12,87,497/-	DC, Central Excise, Kalol Division.	15/Ahd-III/2016-17
2	5609-5615/CE/ Reb/DC/15-16 dated 21.3.2016	Rs. 15,43,924/-	-do-	16/Ahd-III/2016-17

2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant, filed two rebate claims as merchant exporter, in respect of goods manufactured by M/s. Swiss Polyplast. Show cause notices were issued to the appellant, *inter-alia*, asking him to show cause as to why the claims, should not be rejected and export documents be cancelled under notification No. 21/2011-CE(NT) dated 14.9.2011 read with Rule 12(5) of Central Excise Rules, 2002.

3. On the claims being rejected vide the aforementioned OIOs, the appellant has filed these two appeals on the below mentioned grounds:

- the appellant has produced the copy of registration certificate of M/s. Swiss Polyplast;
- since the registration was obtained by M/s. Swiss Polyplast before introduction of ACES, the existing registration should have migrated to ACES;
- that a merchant exporter should not be denied the legitimate claim of rebate for the technical fault of the manufacturer;
- the appellant has also submitted original copy of ARE-1s, copy of invoices and copy of CENVAT credit register, as proof of payment;
- that they have made numerous representation with the department to rectify their matter, but it was rectified only on 2.2.2016;
- that non filing of returns by manufacturer, should not be a ground to deny rebate to merchant exporter;
- that the manufacturer has now filed all the returns electronically;
- the impugned orders does not mention that verification was not possible with the CENVAT register to ascertain that the goods were cleared on payment of duty;
- that technical interpretation of procedures is to be avoided if the substantive fact of export having been made is not in doubt, a liberal interpretation is to be given in case of technical lapse;
- that it is no where mentioned in the notice or in the impugned orders that the appellant had contravened the provisions or procedures mentioned in the notification No. 19/2004-CE(NT).

4. Personal hearing in the matter was held on 20.12.2016. Shri M.G.Raval, Consultant, appeared on behalf of the appellant, and reiterated the arguments made in



the grounds of appeal. He also submitted written submissions, raising similar contentions which were already raised in the grounds of appeal.

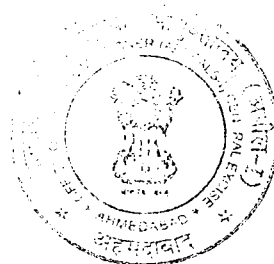
5. I have gone through the facts of the case, the grounds of appeal and the oral averments, raised during the course of personal hearing.

6. The adjudicating authority, in both these cases has rejected the rebate on the grounds that:

- M/s. Swiss Polyplast never took up the matter with ACES helpdesk, which is the proper forum to issue user ID and password; that they approached the proper authority only in the month of September 2015;
- that as per CBEC's supplementary manual, before sanctioning rebate claim the sanctioning authority should satisfy himself regarding duty paid character of the goods that have been exported;
- M/s. Swiss Polyplast claim that they had filed all the returns manually is not correct;
- that subsequently they had filed all the returns electronically; that it is observed that there is an accumulated balance of Rs. 15.5 lacs at the end of May 2015; that it appears that the goods have been cleared under claim of rebate to encash the accumulated balance of CENVAT Credit;
- a detailed study revealed that it was not possible to justify accumulation of such a CENVAT credit and payment of central excise duty amount of such accumulated CENVAT credit;
- that the jurisdictional Superintendent has expressed his inability to certify the duty payment beyond doubt.

7. Rebate of duty, in case of export of goods, is governed by Rule 18 of the Central Excise Rules, 2002 read with notification No. 19/2004-CE(NT) dated 6.9.2004, as amended. The procedure spelt out is that the excisable goods are required to be cleared for export under ARE-I form. Original and duplicate copies contain the certification from customs authorities that said goods are exported vide relevant Shipping Bill. The triplicate copy of ARE-I contains the duty payment certification from Range Superintendent. Thus, it becomes quite clear that ARE-1 is the basic essential document for export of duty paid goods under rebate claim. The Customs certification on these copies of ARE-1 proves the export of goods. The rebate sanctioning authority has to compare these documents with triplicate copy of ARE-1, as stipulated vide Notification No. 19/2004-C.E. (N.T.), dated 6-9-2004, to satisfy himself about the correctness of the rebate claim, to establish that excisable goods cleared from factory of manufacture on payment of duty has been exported.

8. I find that as per the procedure which has been laid down in the notification, *ibid*, and in CBEC's Manual of Supplementary Instructions, to facilitate the processing of a rebate application, the two fold requirement are [i] of the goods having been exported and [ii] of the goods bearing a duty paid character is fulfilled. The appellant has enclosed photo copy of all the ARE-1s. In case of some of the ARE-1s, the jurisdictional range Superintendent has stated under Part A that the



payment particulars are not verified. I find that the only reason for rejecting the rebate is that the jurisdictional Superintendent has expressed his inability to certify the duty payment beyond doubt. There is however, no dispute regarding export of goods.

9. The reasoning as is spelt out in the impugned OIOs for the jurisdictional Superintendent expressing his inability to certify the duty payment, beyond doubt, is probably owing to the accumulated balance of Rs. 15.5 lacs at the end of May 2015 in the CENVAT account of the manufacturer [M/s. Swiss Polyplast]. The impugned OIOs, further lists four reasons based on a detailed study that was conducted for arriving at such a conclusion. However, the result of the study is presented without proper reasoning, or following the principles of natural justice, forcing one to conclude that these are probably assumptions. Surprisingly, if the availment was doubtful, which is also backed by the detailed study, to say the least, immediate remedial action of issuing a show cause notice should have been resorted to, - to safeguard revenue. However, there is no such action either initiated or proposed, which finds a mention in the findings. I find that the rebate has been unjustly denied to the appellant, based on presumptions and assumptions against M/s. Swiss Polyplast.

10. Considerable time has passed since M/s. Swiss Polyplast, filed all the returns, electronically. As the balance lying in the CENVAT credit account was doubted, [as is mentioned in the impugned OIO], a natural corollary would be that a notice would have been issued to M/s. Swiss Polyplast, seeking to deny CENVAT credit wrongly availed. Further owing to the time gap, this notice would also have been adjudicated. So, it would be in the interest of justice if the matter relating to the rebate claim, which was denied doubting the duty payment character of the goods, is remanded to the adjudicating authority, with a direction to pass an order on the said claim after taking into consideration the merits of the case and also the findings as far as wrong availment of CENVAT Credit, is concerned. But after having said so, in case, no such notice has been issued for wrong availment till date, I feel, it would **not** be legal to deny the rebate to the appellant-merchant exporter, on the grounds of mere assumptions.

11. In view of the foregoing, both the impugned OIOs dated 18.3.2016 and 21.3.2016, are set aside by way of remand to the adjudicating authority. The adjudicating authority, needless to state will follow the directions given *supra*. The appellant is further directed to provide all the documents sought by the adjudicating

